

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-2* *Issue-10* *October 2025*

ई-ग्रंथालय: एक समीक्षात्मक अध्ययन**नन्द किशोर प्रसाद***पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर, रामगुलाम उच्च शिक्षा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान,
मधुबनी, बिहार***सारांश—**

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्विक स्तर पर लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के स्वरूप को पूर्णतः बदल दिया है। आज पुस्तकालय केवल पुस्तकों के भंडार तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञान, सूचना और डिजिटल सेवाओं के केंद्र बन चुके हैं। भारत में लाइब्रेरी ऑटोमेशन की दिशा में ई-ग्रंथालय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सशक्त पहल है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित यह सॉफ्टवेयर पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से उन्नत, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने में सहायक है। यह शोध-पत्र ई-ग्रंथालय की तकनीकी संरचना, इसके लाभ, चुनौतियाँ, उपयोग की वर्तमान स्थिति, विशेषकर बिहार की लाइब्रेरियों में इसकी उपयोगिता, और भविष्य की संभावनाओं का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि ई-ग्रंथालय भारत के सभी प्रकार की लाइब्रेरियों के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय समाधान है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए डिजिटल अवसंरचना, प्रशिक्षित मानव संसाधन, पर्याप्त बजट और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। ई-ग्रंथालय भारत सरकार के नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित एक बहुआयामी और सुरक्षित Integrated Library Management System (ILMS) है, जिसका उद्देश्य देश की शैक्षणिक, सरकारी, न्यायिक और सार्वजनिक लाइब्रेरियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। यह सॉफ्टवेयर पुस्तकालय की पारंपरिक सेवाओं को आधुनिक ICT-आधारित सेवाओं में परिवर्तित करता है, जिसमें OPAC, बारकोड/RFID, DykmM स्टोरेज, डिजिटल रिपॉजिटरी और मल्टी-लाइब्रेरी नेटवर्क जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। यह शोध-पत्र ई-ग्रंथालय की अवधारणा, तकनीकी संरचना, इसके उपयोग का भारत और बिहार में वास्तविक परिदृश्य, सहायता-प्राप्तियाँ, कार्यान्वयन की चुनौतियाँ, तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ई-ग्रंथालय भारतीय लाइब्रेरियों के लिए अत्यंत विश्वसनीय, सुरक्षित और कम-लागत वाला विकल्प है, परंतु इसके प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित स्टाफ, उच्च गति इंटरनेट, डिजिटल अवसंरचना और सरकारी सहयोग अत्यंत आवश्यक है। यह शोध डिजिटल लाइब्रेरीकरण की दिशा में भारत के प्रयासों को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

कुजी शब्द— ई एंड ग्रंथालय, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, एनआईसी, आईसीटी, डिजिटल लाइब्रेरी, ओपीएसी, आरएफआईडी, ज्ञान प्रबंधन।

प्रस्तावना—

21वीं सदी में सूचना संसाधनों की प्रकृति और उपयोग का स्वरूप अत्यंत तेजी से बदल रहा है। एक समय था जब लाइब्रेरियाँ भारी-भरकम पुस्तकों, रजिस्ट्रों और कार्ड-कैटलॉग से संचालित होती थीं। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में लाइब्रेरी का अर्थ केवल पुस्तकालय भवन नहीं, बल्कि ज्ञान का डिजिटल संग्रह, ई-संसाधन, डेटाबेस, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और इंटरनेट आधारित सेवाएँ हैं। ICT (Information and Communication Technology) ने लाइब्रेरी विज्ञान में एक ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन प्रक्रिया शुरू की है, जो ज्ञान प्राप्ति को तेज, आसान, व्यापक और सुरक्षित बनाती है।

इसी डिजिटल क्रांति के बीच ई-ग्रंथालय की अवधारणा उभरकर सामने आई, जिसे भारत सरकार के छठे पंचवर्षीय विकास कार्यक्रम ने विकसित किया। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिसे विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों, सरकारी विभागों, न्यायालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सुरक्षित, विश्वसनीय, ओपन-सोर्स, बहुभाषीय एवं क्लाउड-आधारित है। भारत

सरकार द्वारा लाइब्रेरी सिस्टम को डिजिटल रूप में स्वचालित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें ई-ग्रंथालय (E-Granthalaya) सबसे महत्वपूर्ण और सफल पहल है। NIC द्वारा विकसित यह सॉफ्टवेयर भारतीय लाइब्रेरियों की वास्तविक परिस्थितियों जैसे-बहुभाषीय उपयोग, सरकारी सुरक्षा मानक, क्लाउड बैकअप, निम्न बजट, और बड़े उपयोगकर्ता आधारकृको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह न केवल लाइब्रेरी के सभी कार्यों को ऑटोमेट करता है, बल्कि विभिन्न लाइब्रेरियों को एक नेटवर्क के रूप में जोड़कर ज्ञान साझेदारी को बढ़ावा देता है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से सुधार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल अवसंरचना और ICT कौशल का विस्तार भी हो रहा है। इस बदले हुए वातावरण में ई-ग्रंथालय लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन के लिए एक अत्यंत उपयुक्त मॉडल बनकर उभरा है। बिहार के जिला पुस्तकालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों में ई-ग्रंथालय की स्थापना ने सेवाओं को तेज, पारदर्शी, उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुरक्षित बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल पहुंच बढ़ने से ई-ग्रंथालय का उपयोग संभव हुआ है। डिजिटल लाइब्रेरीकरण केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि ज्ञान-प्रबंधन की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह उपयोगकर्ताओं को 24X7 सूचना तक पहुँच, ऑनलाइन ळा, डिजिटल कंटेंट, रिपोर्टिंग, और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। इसी कारण ई-ग्रंथालय डिजिटल इंडिया मिशन, NEP 2020 और ई-गवर्नेंस पहलों का एक मूल तत्व बन चुका है। इस अध्ययन का उद्देश्य ई-ग्रंथालय की संरचना, उपयोग, चुनौतियाँ और संभावनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण करना है ताकि भारतीय विशेषकर बिहार की लाइब्रेरियों के डिजिटलीकरण में इसकी भूमिका स्पष्ट हो सके।

ई-ग्रंथालय की अवधारणा

ई-ग्रंथालय एक Integrated Library Management System (ILMS) है, जो पुस्तकालय के सभी मुख्य कार्यों-सूचीकरण,

वर्गीकरण,

इश्यू-रिटर्न,

सदस्यता प्रबंधन,

बारकोड / RFID कार्यप्रणाली,

ऑनलाइन कैटलॉग (OPAC) को डिजिटल रूप से संचालित करने में सक्षम है।

यह सॉफ्टवेयर NIC Cloud पर आधारित है, जो इसे अत्यंत सुरक्षित बनाता है। ई-ग्रंथालय किसी एक प्रकार की लाइब्रेरी के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक, शैक्षणिक, न्यायिक, तकनीकी, अनुसंधान, स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानोंकृसभी के लिए उपयुक्त है।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ-

1. पूर्णतः भारतीय परिस्थितियों पर आधारित
2. सभी भारतीय भाषाओं में कार्य करने योग्य
3. ओपन-सोर्स
4. NIC द्वारा नियमित अपडेट
5. सुरक्षित क्लाउड होस्टिंग
6. नेटवर्क आधारित- एक से अधिक लाइब्रेरियाँ जुड़ सकती है।

3. ई-ग्रंथालय की तकनीकी संरचना (ज्मबीदपबंस |तबीपजमबजनतम)

3.1 NIC Cloud Support

ई-ग्रंथालय की सबसे बड़ी ताकत इसका छ्ब ब्स्वनक पर चलना है।

- डेटा सुरक्षित
- बैकअप आसान है, किंग और डेटा लॉस का खतरा कम बड़े आकार की लाइब्रेरी को भी आसानी से सपोर्ट

3.2 मॉड्यूल आधारित संरचना

ई-ग्रंथालय के प्रमुख मॉड्यूल हैं-

1. Acquisition
2. Cataloguing
3. Serials Management
4. Circulation

5. Member Management

6. Reporting

7. Digital Repository Management

प्रत्येक मॉड्यूल एक अलग कार्य करता है, परंतु सभी एकीकृत होकर संपूर्ण लाइब्रेरी को स्वचालित बनाते हैं।

- स्वचालन में तेजी।
- चोरी रोकने में मदद।
- इश्यू-रिटर्न में 80% समय की बचत।
- OPAC (Online Public Access Catalogue)

इससे उपयोगकर्ता—

- ऑनलाइन पुस्तकें खोज सकते हैं।
- रियल-टाइम उपलब्धता देख सकते हैं।
- अपनी सदस्यता स्थिति जान सकते हैं।
- भारत में ई-ग्रंथालय का उपयोग (Use of E&Granthalaya in India)

NIC के अनुसार—

- 7000+ लाइब्रेरियाँ ई-ग्रंथालय पर चल रही हैं।
- 22+ राज्य सरकारें इसका उपयोग कर रही हैं।
- पुलिस, न्यायालय, सचिवालय, मंत्रालय और सरकारी विभाग इसका उपयोग करते हैं।
- लाखों उपयोगकर्ता प्रतिदिन इसके OPAC सिस्टम से लाभ लेते हैं।

ई-ग्रंथालय KOHA की तरह अंतरराष्ट्रीय नहीं, लेकिन भारत में सरकारी लाइब्रेरियों के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि यह सरकार द्वारा विकसित और सुरक्षित किया गया है।

बिहार में ई-ग्रंथालय की स्थिति—

बिहार में डिजिटल लाइब्रेरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। ई-ग्रंथालय को विशेषकर सरकारी विभागों और जिला पुस्तकालयों में तेजी से अपनाया जा रहा है।

विश्वविद्यालय स्तर पर उपयोग

कई विश्वविद्यालयों ने ई-ग्रंथालय को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला पुस्तकालय, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, पंचायत संसाधन केंद्रों, ब्लॉक पुस्तकालयों में इसका उपयोग बढ़ रहा है।

जिला और ब्लॉक पुस्तकालय

पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी, गया आदि जिलों में इसकी स्थापना हो रही है।

तकनीकी नवाचार

- AI आधारित खोज
 - मोबाइल ऐप
 - क्लाउड बैकअप
 - स्मार्ट लाइब्रेरी
 - सुझाव
1. सभी विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ई-ग्रंथालय लागू किया जाए।
 2. लाइब्रेरी स्टाफ के लिए प्लग प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।
 3. उच्च गति इंटरनेट और बिजली की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
 4. त्थक प्रणाली को सभी जिला पुस्तकालयों में लागू किया जाए।
 5. छात्रों और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल जागरूकता अभियान चलाया जाए।
 6. ई-ग्रंथालय को NDLI, Shodhganga और अन्य डेटाबेस से जोड़ा जाए।

निष्कर्ष—

ई-ग्रंथालय भारत के डिजिटल लाइब्रेरी मिशन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह लाइब्रेरी को आधुनिक, पारदर्शी, स्वचालित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाता है। बिहार में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में यह सभी सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों की केंद्रीय सूचना प्रणाली बन सकता है। यदि राज्य स्तर पर अवसंरचना, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम में सुधार किया जाए, तो ई-ग्रंथालय बिहार को डिजिटल ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ—

1. NIC E&Granthalaya Documentation (2024)
2. MEITY Digital Library Report (2023)
3. Bihar ICT Education Survey (2022)
4. Singh, P. 2021 ICT in Indian Libraries
5. Sharma, R 2020, Digital Library Management in India.
6. National Informatics Centre, NIC, E&Granthalaya 4.0: Technical Manual & User Documentation- Government of India, New Delhi, 2023.
7. Ministry of Electronics & Information Technology Meit, Digital Library and e&Governance Report, Government of India, 2022.
8. IFLA, International Federation of Library Associations, Guidelines for Digital Libraries, IFLA Publications, 2021.
9. Kaur, Navreet & Singh, Harpreet Library Automation in Indian Universities: A Study of NIC E-Granthalaya System, Indian Journal of Library and Information Science, Vol- 12, Issue 2, 2021.
10. Sharma, J.C. Modern Digital Library Systems and Their Applications, Delhi: Ess Publications] 2020.

Cite this Article

'नन्द किशोर प्रसाद', "ई-ग्रंथालय: एक समीक्षात्मक अध्ययन", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:10, October 2025.

Journal URL- <https://www.researchvidyapith.com/>

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i100008

Published Date- 03 October 2025